

नरिवाचन आयोग ने कथिा स्पष्ट : सभी राजनीतिक पारटियों RTI के दायरे में

चर्चा में क्यों?

चुनाव आयोग ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रीय पारटियों सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने एक RTI का जवाब देते हुए कहा था कि राजनीतिक पारटियों RTI कानून के दायरे में नहीं आती हैं।

महत्त्वपूर्ण बडि

- चुनाव आयोग ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 3 जून, 2013 के नरिणय के अनुसार RTI कानून से जुड़े सार्वजनिक प्राधिकरण हैं।
- छह राष्ट्रीय दलों- भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राकांपा, भाकपा, माकपा को 3 जून, 2013 को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था।
- सितंबर, 2016 में तृणमूल कांग्रेस को इसके अंतर्गत सातवें दल के रूप में मान्यता दी गई थी।
- CIC द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि इन पारटियों द्वारा प्राप्त कथिे गए चंटे के साथ-साथ इन सभी पारटियों के वार्षिक लेखा खातों की सूचना, आयोग को कब सौंपी गई, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी।
- हालांकि उच्च न्यायालयों में इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उन पर नरिदेशति RTI आवेदनों पर वचिार करने से इंकार कर दथिा है।

नरिवाचन आयोग

- नरिवाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक नकिया है।
- संवधान के अनुसार नरिवाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।
- प्रारंभ में, आयोग में केवल एक मुख्य नरिवाचन आयुक्त था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य नरिवाचन आयुक्त और दो नरिवाचन आयुक्त होते हैं।
- पहली बार दो अतरिकित आयुक्तों की नयिकृति 16 अक्टूबर, 1989 को की गई थी लेकिन उनका कार्यकाल 01 जनवरी, 1990 तक ही चला। उसके बाद 01 अक्टूबर, 1993 को दो अतरिकित नरिवाचन आयुक्तों की नयिकृति की गई थी, तब से आयोग की बहु-सदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जसिमें नरिणय बहुमत के आधार पर लथिा जाता है।

सूचना का अधिकार (RTI)

- संसद ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारति कथिा था।
- इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि कसि प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और कसि प्रकार सरकार जवाबदेह होगी।
- सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कथिह -

- ◆ सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके।
- ◆ कसि भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणति प्रत ले सके।
- ◆ कसि भी सरकारी दस्तावेज की जाँच कर सके।
- ◆ कसि भी सरकारी काम की जाँच कर सके।
- ◆ कसि भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणति नमूना ले सके।

केंद्रीय सूचना आयोग

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अध्याय-तीन, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय-चार में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष अरथात् मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। इनकी नयिकृति राष्ट्रपतिद्वारा की जाती है।

पृष्ठभूमि

3 जून, 2013 को अपने फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था, "राजनीतिक पारटियों के चंटे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जनता की दलिचस्पी रहती

है। इससे वोट देते वक़्त सही फैसला लेने में भी मदद होगी। लोकतंत्र के सुचारु रूप से चलने के लिये पारदर्शिता ज़रूरी है। राजनीतिक दल राजनीतिक शक्त के नरिवाह में अहम भूमिका नभिते हैं, ऐसे में उनका पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह होना जनहति में है।"

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ec-takes-u-turn-clarifies-that-it-abides-by-cic-ruling-that-political-parties-are-under-rti-ambit>

